



# स्मरणीय तथ्य

# राजव्यवस्था एवं शासन



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची

# फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

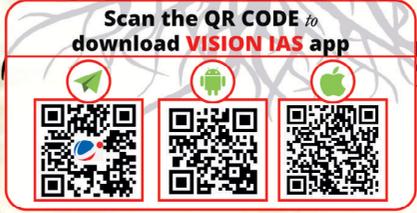
- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM

JAIPUR : 24 जून

JODHPUR : 2 जुलाई



## ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध



2025

ENGLISH MEDIUM  
6 JULY

हिन्दी माध्यम  
6 जुलाई

2026

ENGLISH MEDIUM  
6 JULY

हिन्दी माध्यम  
6 जुलाई

# विषय सूची

1. समान नागरिक संहिता (UCC) . . . . .	5	16. जेल सुधार . . . . .	7
2. संपत्ति का अधिकार . . . . .	5	17. डिजिटल फॉर्मेट पर अश्लीलता . . . . .	8
3. राज्यों की स्वायत्तता . . . . .	5	18. फ्रीबीज/ मुफ्त सुविधाएं . . . . .	8
4. जातिगत जनगणना . . . . .	5	19. भारत निर्वाचन आयोग . . . . .	8
5. नागरिकता . . . . .	5	20. राज्य चुनाव आयोग . . . . .	8
6. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व . . . . .	6	21. परिसीमन आयोग . . . . .	8
7. संसद और राज्य विधान-मंडलों के कामकाज में गिरावट (PRS रिपोर्ट) . . . . .	6	22. सहभागी गवर्नेंस . . . . .	8
8. लोक सभा उपाध्यक्ष का पद . . . . .	6	23. पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संवैधानिकीकरण . . . . .	9
9. नए राज्यों के गठन की मांग . . . . .	6	24. शक्तियों का अंतरण (Devolution) . . . . .	9
10. दल-बदल विरोधी कानून . . . . .	6	25. गैर-सरकारी संगठन (NGOs) . . . . .	9
11. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र . . . . .	7	26. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) . . . . .	9
12. भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली . . . . .	7	27. इंटरनेट शटडाउन . . . . .	9
13. निःशुल्क विधिक सहायता . . . . .	7	28. भारत में सहकारी समितियां . . . . .	10
14. राजनीति का अपराधीकरण . . . . .	7	29. सूचना का अधिकार (RTI) . . . . .	10
15. भारत में अधिकरण . . . . .	7	30. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान . . . . .	10



**MAINS**  
**365**

**ENGLISH MEDIUM**  
**1 July | 5 PM**

**हिन्दी माध्यम**  
**5 July | 5 PM**

- ✍ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- ✍ मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- ✍ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड-वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- ✍ लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

**मुख्य परीक्षा**  
2025 के लिए 1 वर्ष का  
**समसामयिक घटनाक्रम**  
केवल 60 घंटे में



## प्रिय अभ्यर्थियों,

-  UPSC मुख्य परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके उत्तरों में आंकड़े, तथ्यों और उदाहरणों को शामिल करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
-  ये घटक एक आकर्षक और प्रेरक अनुक्रिया के आधार के रूप में काम करते हैं, जो आपके उत्तर को एक सामान्य लेखन से एक बेहतर तरीके से प्रमाणित तर्क की ओर ले जाते हैं।
-  आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS के Mains 365 पठन सामग्री से सार रूप में आंकड़े, तथ्यों और उदाहरणों का संकलन तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है Mains 365 पठन सामग्री करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
-  राजव्यवस्था एवं शासन से संबंधित यह डाक्यूमेंट उच्च गुणवत्ता वाले तथ्यों, आंकड़ों, पहलों आदि का एक संक्षिप्त एवं लक्षित संकलन प्रस्तुत करता है। UPSC मुख्य परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रासंगिक और अपडेटेड जानकारी से सुसज्जित रहना आवश्यक है, जो आपके उत्तरों को अधिक प्रभावशाली और विश्लेषणपरक बना सके।
-  इस डाक्यूमेंट का लेआउट आपके उत्तर में क्विक रेफरेंस और तथ्यों आदि के आसान समेकन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
-  इस सार रूपी जानकारी का लाभ उठाने से आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यापक, सूचनात्मक और आकर्षक उत्तर तैयार करने में मदद मिलेगी।



↓  
Mains 365 डाक्यूमेंट्स को  
डाउनलोड करने के लिए  
दिए गए QR कोड को स्कैन  
कीजिए



स्मार्ट क्वालिटी कंटेंट को  
प्राप्त करने के लिए दिए  
गए QR कोड को स्कैन  
कीजिए



# ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव  
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र



**2025**

**ENGLISH MEDIUM**  
**6 JULY**

**हिन्दी माध्यम**  
**6 जुलाई**

**2026**

**ENGLISH MEDIUM**  
**6 JULY**

**हिन्दी माध्यम**  
**6 जुलाई**

Scan the QR CODE to  
download **VISION IAS** app





## जातिगत जनगणना

- ◆ अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 69) के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है।
- ◆ अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है।
- ◆ जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
- ◆ जस्टिस रोहिणी आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।



## नागरिकता

- ◆ अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
- ◆ अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- ◆ अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने से संबंधित अधिकार है।
- ◆ अनुच्छेद 11: संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित कर सकती है।



## समान नागरिक संहिता (UCC)

- ◆ अनुच्छेद 44: राज्य को समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है।
- ◆ अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता): UCC के विरुद्ध तर्क के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ◆ शाह बानो बेगम (1985) और सरला मुद्गल (1995) वाद में समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता पर बल दिया।
- ◆ 21वें विधि आयोग (2018) ने कहा था कि इस समय UCC का निर्माण आवश्यक या वांछनीय नहीं है।



## संपत्ति का अधिकार

- ◆ अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। आरंभ में यह अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत एक मूल अधिकार था।
- ◆ 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया।
- ◆ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद: इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित किया है।
- ◆ टी. एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ वाद: सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के अनुसार, राज्य एक ट्रस्टी के रूप में सार्वजनिक लाभ के लिए संसाधनों का प्रबंधन करता है।



## राज्यों की स्वायत्तता

- ◆ राजमन्जार समिति (1969): इस समिति ने सातवीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग के गठन की सिफारिश की थी।
- ◆ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973): केंद्र की शक्तियां केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा आदि तक सीमित रखने की मांग की गई, जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात कही गई थी।
- ◆ पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977): अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को हटाने और संविधान में "संघात्मक" शब्द जोड़ने की मांग की गई थी।





## नए राज्यों के गठन की मांग

- ◆ **अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- ◆ **एस. के. धर आयोग (1948):** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
- ◆ **जे. वी. पी. समिति (1948):** इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- ◆ **फजल अली आयोग (1953):** देश की एकता और सुरक्षा; भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता; वित्तीय स्थिरता, आदि के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की।
- ◆ **बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी क्षेत्र को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।



## संसद और राज्य विधान-मंडलों के कामकाज में गिरावट (PRS रिपोर्ट)

- ◆ **अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- ◆ **एस. के. धर आयोग (1948):** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
- ◆ **जे. वी. पी. समिति (1948):** इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- ◆ **फजल अली आयोग (1953):** देश की एकता और सुरक्षा; भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता; वित्तीय स्थिरता, आदि के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की।
- ◆ **बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी क्षेत्र को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।



## दल-बदल विरोधी कानून

- ◆ **इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची को जोड़ा** गया था।
- ◆ **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु वाद (1992):** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए।
- ◆ **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद (2020):** अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए।



## लोक सभा उपाध्यक्ष का पद

- ◆ **अनुच्छेद 93 (चुनाव):** लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद को दिया जाता रहा है।
- ◆ **अनुच्छेद 94:** इसमें पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि लोक सभा उपाध्यक्ष को **सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।**
- ◆ **अनुच्छेद 95:** अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।



## विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- ◆ 18वीं लोक सभा (LS): महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट आई है। 17वीं लोक सभा में इनकी संख्या 78 थी जो 18वीं लोक सभा में घटकर 74 रह गई है। इस प्रकार वर्तमान में कुल संसद सदस्यों का 13.6% महिलाएँ हैं।  
 >> वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 26.9% है।



## भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली

- ♦ **दोषसिद्धि की कम दर:** यह हत्या के मामले में 43.8% और बलात्कार के मामले में 27.4% है। (NCRB 2022)
- ♦ **मामले लंबित:** अदालतों में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं।
- ♦ **विचाराधीन कैदी:** भारत की जेलों में बंद कैदियों की संख्या 75.8% है।
- ♦ **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: भारतीय जेलों की ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है।**
- ♦ **खराब प्रत्यर्पण दर:** केवल 3 में से 1 भगोड़े अपराधी का ही सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया जाता है।
- ♦ **पुलिस कार्मिकों की कमी:** प्रति लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानदंड के अनुसार 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए।
- ♦ **कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात:** प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं।



## निःशुल्क विधिक सहायता

- ♦ **एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है।
- ♦ **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक कैदी को स्पीडी ट्रायल यानी शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है।



## जेल सुधार

- ♦ **मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 और मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023:** राज्यों को जेलों से संबंधित सर्वोत्तम आधुनिक प्रथाओं को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- ♦ **रामामूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामला 1996:** सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिनियम, 1894 को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।



## भारत में अधिकरण

- ♦ **अनुच्छेद 323A:** यह अनुच्छेद संसद को लोक सेवा मामलों के निपटारे के लिए **प्रशासनिक अधिकरण** स्थापित करने का अधिकार देता है।
- ♦ **अनुच्छेद 323B:** विधायिकाओं को कराधान, भूमि सुधार जैसे विशिष्ट विषयों के लिए **अधिकरण** बनाने की अनुमति देता है।
- ♦ **एल. चंद्र कुमार मामला (1997):** इसमें शीर्ष न्यायालय ने सभी अधिकरणों की देख-रेख के लिए एक **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)** की सिफारिश की गई।



## राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

- ♦ **ADR की रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से 46% के खिलाफ आपराधिक** मामले दर्ज हैं।
- ♦ **तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** ने देश में राजनीतिक दलों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- ♦ **विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट):** इसमें गैर-अनुपालन के कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।



## राजनीति का अपराधीकरण

- ♦ **ADR वाद (2002):** इसके तहत मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है।
- ♦ **PUCL वाद (2004):** इसमें धारा 33B को रद्द किया गया, तथा पूर्ण प्रकटीकरण (सूचना साझा करने) के अधिकार को बरकरार रखा गया।
- ♦ **लिली थॉमस वाद (2013):** इस मामले में RPA, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक माना गया; अब **अयोग्यता पर कोई रोक नहीं** लगेगी। प्रचलित सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन किया गया।



## फ्रीबीज/ मुफ्त सुविधाएं

- ♦ **सुब्रमण्यम बालाजी वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पात्र लाभार्थियों को "रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत किया जा सकता है।"
- ♦ **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद):** सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।



## भारत निवचिन आयोग

- ♦ **अनुच्छेद 324:** इसके तहत संसद, राज्य विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों के **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति** भारत निवचिन आयोग को प्रदान की गई है।
- ♦ **गोस्वामी समिति (1990):** सिफारिश की कि **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (ECs)** को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद के लिए अपात्र घोषित किया जाए।
- ♦ **255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट:** अनुच्छेद 324(5) में संशोधन कर CEC और अन्य ECs के हटाए जाने की प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए।



## राज्य चुनाव आयोग

- ♦ **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** में राज्य चुनाव आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी सिफारिश गाडगिल समिति ने भी की थी।
- ♦ **अनुच्छेद 243K (1) और अनुच्छेद 243ZA:** मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निवचिन आयोग में निहित होगा।
- ♦ **अनुच्छेद 243K(2):** राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- ♦ **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हों।



## परिसीमन आयोग

- ♦ **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत,** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए।
- ♦ **संविधान के अनुच्छेद 170** के तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निवचिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।
- ♦ **किशोरचंद्र छागनलाल राठौड़ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि परिसीमन आयोग की कोई सिफारिश स्पष्ट रूप से मनमाना है और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत है, तो संवैधानिक न्यायालय इन सिफारिशों की समीक्षा कर सकता है।



## सहभागी गवर्नेंस

- ♦ **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013:** इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन** का प्रावधान किया गया है।
- ♦ **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** ग्राम सभा की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे **वैधानिक संस्था का दर्जा** दिया गया है।
- ♦ **पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल:** इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है।



## डिजिटल फॉर्मेट पर अश्लीलता

- ♦ **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964)** वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने **हिकलिन** टेस्ट लागू किया। इसके अनुसार "भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति" वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाता है।
- ♦ **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) वाद में,** न्यायालय ने सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया। इसमें



## पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संवैधानिकीकरण

- ♦ **एम. के. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।
- ♦ **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986):** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया।
- ♦ **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है।



## गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

- ♦ **विजय कुमार समिति (2017) की सिफारिशें:** विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण, आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाएं, एक नोडल निकाय की स्थापना, पारदर्शिता के लिए डेटाबेस, स्वयंसेवा की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- ♦ **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:** FCRA के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक क्षेत्रक के संचालन की सुरक्षा के लिए विधायी नियमों का संतुलित और स्पष्ट ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



## शक्तियों का अंतरण (Devolution)

- ♦ **अनुच्छेद 243G:** राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं।
- ♦ **अनुच्छेद 243H:** राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, टोल, फीस एकत्र करने का अधिकार देता है।
- ♦ **अनुच्छेद 243I:** यह पंचायतों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- ♦ **अनुच्छेद 243ZD:** यह पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने हेतु एक जिला विकास योजना बनाई जाती है।



## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

- ♦ **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2019:** केंद्र सरकार निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर CBI निदेशक की नियुक्ति करेगी-
  - » प्रधान मंत्री (अध्यक्ष);
  - » विपक्ष का नेता (लोक सभा) या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता (सदस्य); तथा
  - » भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश (सदस्य)।
- ♦ **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी, 2024:** दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि CBI को RTI अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, RTI अधिनियम के तहत उसे मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी प्रकट करनी होगी।



## इंटरनेट शटडाउन

- ♦ **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** वर्ष 2017 तक CrPC की धारा 144 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163) के तहत।
  - » जिला मजिस्ट्रेट को गैर-कानूनी सभा रोकने/ गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं।
- ♦ **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति के अलावा कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा आदि बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार देता है।
- ♦ **फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामला:** केरल हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
- ♦ **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता की पुष्टि की।



## भारत में सहकारी समितियां

- ◇ उत्पत्ति: भारत में सहकारिता **कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904** के साथ शुरू हुई थी।
- ◇ **वर्तमान स्थिति:** भारत में विश्व की **27% सहकारी समितियां हैं।**
- ◇ **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक:** आवास; डेयरी; और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।
- ◇ **अग्रणी राज्य:** महाराष्ट्र (25%), गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।
- ◇ **संवैधानिक स्थिति:** 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है-
  - » **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 19(1)(c)
  - » **राज्य नीति निदेशक तत्व:** अनुच्छेद 43B जोड़ा गया
  - » **नया भाग IXB:** अनुच्छेद 243ZH-243ZT
- ◇ गवर्नेंस संरचना:
  - » **बहु-राज्य समितियां:** ये संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती हैं और इन्हें **बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002** के तहत शासित किया जाता है।
  - » **राज्य सहकारी समितियां:** ये राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं और इन्हें संबंधित **राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों** के तहत शासित किया जाता है।



## सूचना का अधिकार (RTI)

- ◇ **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2004):** इसमें सूचना के अधिकार को **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया। इस निर्णय ने आगे चलकर RTI अधिनियम, 2005 का मार्ग प्रशस्त किया।
- ◇ **नमित शर्मा बनाम भारत संघ (2013):** कोर्ट ने माना कि सूचना आयोग एक **अर्ध-न्यायिक** संस्था है, यानी यह अदालत की तरह काम कर सकती है।
- ◇ **2nd ARC की सिफारिशें: राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC)** का गठन किया जाए; RTI के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- ◇ **जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018):** धारा 8(1)(j) के तहत सूचना ना देने के कारणों को सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की। केवल वहीं सूचना ना दी जाए जहाँ वास्तव में **गंभीर नुकसान** हो सकता हो, जैसे: पहचान की चोरी, भेदभाव आदि।



## अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान

- ◇ **अनुच्छेद 30(1) भाषाई** और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- ◇ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30(1)** में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।



**OUR ACHIEVEMENTS**



**LIVE/ONLINE**  
Classes Available  
[www.visionias.in](http://www.visionias.in)



**Foundation Course**  
**GENERAL STUDIES**  
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 30 JUNE, 8 AM | 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM  
18 JULY, 5 PM | 22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम 15 जुलाई, 2 PM

AHMEDABAD: 7 JUNE

BENGALURU: 20 JUNE

BHOPAL: 27 JUNE

CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 14 JULY

JAIPUR: 24 JUNE

JODHPUR: 2 JULY

LUCKNOW: 24 JUNE

PUNE: 16 JUNE

**फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026**

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM

JAIPUR : 24 जून

JODHPUR : 2 जुलाई

प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/channel/UCVisionIASdelhi)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.instagram.com/visioniasdelhi)

[/t.me/s/VisionIAS\\_UPSC](https://t.me/s/VisionIAS_UPSC)

# Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

# 10

in TOP 10 Selections in CSE 2024

from various programs of Vision IAS



1  
AIR

Shakti Dubey



2  
AIR

Harshita Goyal

GS Foundation  
Classroom Student



3  
AIR

Dongre Archit Parag

GS Foundation  
Classroom Student



4  
AIR

Shah Margi Chirag



5  
AIR

Aakash Garg



6  
AIR

Komal Punia



7  
AIR

Aayushi Bansal



8  
AIR

Raj Krishna Jha



9  
AIR

Aditya Vikram Agarwal



10  
AIR

Mayank Tripathi

## हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में



137  
AIR

Ankita Kanti



182  
AIR

Ravi Raaz



438  
AIR

Mamata



448  
AIR

Sukh Ram



509  
AIR

Amit Kumar Yadav



### HEAD OFFICE

33, Pusa Road,  
Near Karol Bagh Metro Station,  
Opposite Pillar No. 113,  
Delhi - 110005

DELHI

### MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,  
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab  
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

### GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,  
above Gate No. 2, GTB Nagar  
Metro Building, Delhi - 110009

### FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:  
+91 8468022022,  
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



/@visioniashindi



/visionias.upsc



/vision\_ias\_hindi/



/hindi\_visionias



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची